

ट्रम्प प्रशासन ने एमेज़ॉन को “धमकी” दी

घबराकर एमेज़ॉन ने अपनी कीमतों में टैरिफ वॉर के कारण हुई वृद्धि को दिखाने का इरादा त्याग दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। एक बेहद अजीब घटनाक्रम में, ट्रंप प्रशासन अमेरिका की सबसे सफल कंपनियों में से एक के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहा है, वजह यह है कि कंपनी अपने उत्पादों की कीमत में यह दिखाना चाहती थी कि टैरिफ के कारण मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है।

एमेज़ॉन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ऑनलाइन सैलर (विक्रेता) है, उपभोक्ताओं के लिए मूल्य निर्धारण का यह नया विवरण पेश करने की योजना बना रहा था। लेकिन लगता है कि इसकी धनक लगने के बाद, यू.एस. एडमिनिस्ट्रेशन ने धमकी भरे संकेत दिए, जिससे एमेज़ॉन डर गया।

यह एक विडंबना है, क्योंकि अमेरिका, पूंजीवाद और बड़ी कंपनियों का गढ़ था तथा खासकर अत्यधिक सफल तकनीकी कंपनियाँ, देश की “पवित्र गायें” मानी जाती थीं। इनकी वाहवाही होती थी तथा इन कंपनियों के सीईओ कभी अमेरिका की कॉर्पोरेट संस्कृति में सेलेब्रिटी हुआ करते थे।

लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद

- वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने एमेज़ॉन द्वारा टैरिफ वॉर को मूल्य वृद्धि का कारण बताने को “राजनीति व गैर मैत्रीपूर्ण” कार्यवाही बताया। प्रेस सचिव ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी राष्ट्रपति ट्रम्प से भी बात हो चुकी है।
- ट्रम्प सरकार की इस “धमकी” के आगे, एमेज़ॉन का हौंसला पस्त हुआ और एमेज़ॉन ने “प्राइस राइज़” पर टैरिफ नीति का प्रभाव जताने का इरादा त्याग दिया।
- पर, यह भी सच है कि ट्रम्प की नई टैरिफ नीति के कारण, अमेरिका में मूल्य वृद्धि तो हुई ही है, साथ ही नौकरियां खत्म हो रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है और इस समय जानी-मानी कंपनी एमेज़ॉन द्वारा यदि यह प्रचारित किया जाता कि ट्रम्प की नई टैरिफ नीति, इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है, तो ट्रम्प प्रशासन के लिए दिक्कतें बढ़ सकती थीं।

यह पूरी तस्वीर बदल गई है। सरकार अब उन शीर्ष कंपनियों के साथ टकराव की स्थिति में है, जो उसकी आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रही हैं। कुछ प्रमुख कंपनियों को आशंका है कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है।

वाइट हाउस की प्रेस सचिव

मूल्य में वृद्धि का कितना हिस्सा शुल्कों के कारण है।

डॉनल्ड ट्रंप ने अपना चुनाव प्रचार इस आधार पर लड़ा था कि रोजमर्रा की चीजों को कीमते तेजी से बढ़ रही हैं और आम अमेरिकी की पहुँच से बाहर हो रही हैं। यह मुद्दा उनकी अपील की एक प्रमुख वजह था।

तथापि, अब जब टैरिफ लागू हो चुके हैं, कीमते लगातार बढ़ रही हैं। आम अमेरिकी अब ट्रंप प्रशासन से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं।

स्थिति और भी गंभीर हो रही है, क्योंकि मंदी आने से पहले ही नौकरियां जा रही हैं और सबसे बुरी बात, यह शुरुआत संघीय सरकार की नौकरियों से हुई है। इन नौकरियों को अब तक स्थायी और सुरक्षित माना जाता था। लेकिन ट्रंप शासन में ये भी असुरक्षित हो गई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएन्सी के हमले से चरमराने लगी है।

कुछ अनुमानों के अनुसार, अमेरिकी संघीय सरकार में ढाई लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जबकि कुछ अन्य अनुमानों में यह संख्या डेढ़ लाख बताई गई है। रिटेल सेक्टर ने भी करीब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नगर पालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं

जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके चुनाव नहीं कराने और प्रशासक नियुक्त करने पर राज्य के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब माँगा है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अदालत को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 243 यू और नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 और धारा 11 के तहत नगरपालिकाओं का

- **हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा।**

कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, उनके चुनाव कराए जाने जरूरी है। नगरपालिका अधिनियम के तहत, पिछले बोर्ड की पहली बैठक के पांच साल पूरे होने से पहले चुनाव होने चाहिए। प्रदेश की नगरपालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर, 2024 को पूरा हो चुका है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने इन नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के बजाए यहां प्रशासक लगा दिए। याचिका में यह भी कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं। यदि किसी पालिका बोर्ड का विघटन किया गया है तब भी छह माह के भीतर चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस के पोस्टर की पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने “तारीफ” की!

भाजपा ने इस पर कटाक्ष किया कि अब कांग्रेस केवल पाकिस्तान की भाषा ही नहीं बोलती, अब पाकिस्तान के आदेश पर काम भी करती है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अप्रेल। पहलगाम हमलों के बाद पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए केन्द्र सरकार के जवाबी अभियान के बीच, कांग्रेस ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की जड़ एक पोस्टर है, जिसमें चूड़ीदार पाजामा-कुर्ता पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया है और उस पर लिखा है: “गायब”। हालांकि उस छवि का चेहरा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे तुरंत प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के रूप में पहचान लिया है।

यह विवाद तब और गहरा गया, जब पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने इस पोस्टर को “नॉटी कांग्रेस” हैशटैग के साथ शेयर किया। इसके बाद से भाजपा और इंटरनेट यूज़र्स कांग्रेस की तीखी आलोचना कर रहे हैं और कांग्रेस पर “पाकिस्तान से निर्देश लेने” का आरोप लगा रहे हैं।

पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद खानवाला ने कहा, “यह पार्टी सिर्फ पाकिस्तान जैसी बात ही नहीं करती, बल्कि उनका वर्क कल्चर और

- कांग्रेस के पोस्टर में चूड़ीदार पजामा व कुर्ता पहने एक आदमी दिखाया है, जिसका रंग रूप व काठी प्र.मंत्री मोदी जैसे हैं तथा पोस्टर में कैप्शन दिया है “गायब”। इस पोस्टर में इस व्यक्ति का सिर कटा हुआ दिखाया गया है, जिससे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की गला काटने के “इमेज” का स्मरण होता है।
- पलटवार में भारत ने पाकिस्तान के कई टॉप टी.वी. चैनल्स, जैसे, डॉन न्यूज़, ए.आर.वाय. न्यूज़, समा टीवी व जियो न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाने का इरादा जताया है।
- साथ ही भारत ने इज़रायल की रणनीति अपनाते हुए, वीडियो जारी किये हैं, जिनमें पाकिस्तान की मदद व संरक्षण में आतंकवादियों द्वारा भारत को टारगेट बनाना साफ दिखाया गया है।

व्यवहार भी अब इस्लामाबाद जैसा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक तस्वीर साझा की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सिर नहीं है—यह ठीक वैसा ही है, जैसा लंदन में पाकिस्तान के राजनयिक ने भारतीयों की ओर “गला काटने” का इशारा किया था। कांग्रेस न केवल पाकिस्तान की भाषा

बोल रही है, बल्कि आतंकियों जैसा व्यवहार भी कर रही है।”

पहलगाम हमले के बाद सरकार ने “भारत को निशाना बनाने वाले सूचना “युद्ध” को लेकर चिंता जताई है। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में स्थित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर व बैंक की सांठ-गांठ की जाँच

सीबीआई को सौंपी

दिल्ली, नैशनल कैपिटल रीज़न, मुम्बई, चंडीगढ़, मोहाली व कोलकाता से इस सांठ-गांठ की कई खबरें व शिकायतें आयी थीं, सुप्रीम कोर्ट के पास

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। फ्लैटों /मकानों के निर्माण तथा ग्राहकों को सौंपे जाने में किये जा रहे विलम्ब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, नैशनल कैपिटल रीज़न (एनसीआर), मुम्बई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता के प्रोजेक्टों के मामले में बिल्डरों और बैंकों के बीच की “नापाक साँठ-गाँठ” की सीबीआई जाँच के आदेश दिये हैं।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकान्त तथा एच कोटीश्वर सिंह की बेंच ने सीबीआई को निर्देश दिये कि वह सात प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी (पीई) दर्ज करे तथा एक स्पेशल

- **सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई “प्रिलिमनरी इन्क्वायरी” रजिस्टर करे तथा एक स्पेशल इन्वैस्टिगैटिंग टीम (एसआईटी) गठित करे, जाँच के लिए।**

इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करे।

अदालत ने उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों, जो

राज्य पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, से भी कहा है कि जाँच में सहायता के लिये सीबीआई को पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराये जायें।

जिन कम्पनियों के खिलाफ पीई दर्ज की जायेगी, उनमें से एक है “सुपरटेक”। सर्वोच्च न्यायालय, जो इस केस की मॉनिटरिंग तथा हर महीने सुनवाई करेगा, ने दिल्ली –एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, गुरुग्राम तथा गाजियाबाद में स्थित प्रोजेक्टों की प्रारंभिक जाँच के आदेश दिये हैं।

जिन अन्य बिल्डरों के प्रोजेक्ट दिल्ली–एनसीआर, मुम्बई, चंडीगढ़, मोहाली, कोलकाता में हैं, उनकी भी जाँच होगी। सीबीआई से कहा गया कि वह अन्तरिम स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।

सरिस्का में 3 शावकों के जन्म से टाइगर संख्या 44 हुई

अलवर। अलवर सरिस्का में बाघिन एसटी-30 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। शावकों की उम्र करीब 2 महीने है। अब सरिस्का में टाइगर की संख्या 44 हो गई है।

बता दें कि बाघ पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के तहत बाघिन एसटी-30 को 2023 में रणथम्भौर से सरिस्का लाया गया था और यहां टहलाने रेंज के भगानी

- **जन्म देने वाली बाघिन एसटी-30 को 2023 में रणथम्भौर से सरिस्का पुनर्स्थापित किया गया था।**

में छोड़ा गया था।

सोसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों ने बाघिन एसटी-30 को 3 शावकों के साथ देखा था। शावक और बाघिन स्वस्थ नजर आ रहे हैं। वन विभाग ने अब बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। कैमरा ट्रैप और ग्राउंड पेट्रोलिंग बढ़ाकर मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम किया गया है। बाघिन के नए शावक आने के बाद वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने वनकर्मियों को बधाई दी।

‘सफल इकोनॉमिक्स, सफल राजनीति भी है’

तमिलनाडु के मु.मंत्री ने सोच-समझ कर यह नारा अपनाया है, अगले विधानसभा चुनाव के लिए

-लक्ष्मण बैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को ‘द्रविड़ मॉडल ऑफ डवलपमेन्ट एंड ग्रोथ’ को 2026 के विधानसभा चुनावों के मुख्य आधार के रूप में प्रस्तुत किया तथा यह संदेश देने का प्रयास किया कि अच्छी अर्थव्यवस्था ही अच्छी राजनीति है।

अपना चुनावी नैरेटिव प्रस्तुत करते हुये, स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार के मॉडल का द्वितीय संस्करण 2026 में लोड होगा। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि सत्ता में उनकी वापसी होगी तथा यह एक ऐसी उपलब्धि होगी, जो उनके पिता को भी नसीब नहीं हुई। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों की इस चक्रीय प्रकृति को केवल वे जयललिता ही टोड़ पाई थीं तथा 2011 में द्रमुक से सत्ता छीनने के बाद, 2016 में पुनः निर्वाचित हुई थी।

इस समय, चूँकि विपक्ष कुछ कमजोर है, अनाद्रमुक में फूट है, तथा भाजपा के साथ उसका गठबंधन कभी

- **हालांकि, उनके दो मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं तथा मंत्री पद से हटा दिया गया है। परन्तु, स्टालिन यह जानते हैं कि भ्रष्टाचार चुनाव में कोई खास मुद्दा नहीं होता।**
- **इसका उदाहरण हैं जयललिता, जिन पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगे, पर, वे दोबारा मु.मंत्री चुनकर आयीं।**
- **अतः स्टालिन तमिलनाडु की, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिकीकरण के मामले में सफलता का ही उदाहरण देते हैं और इसे ही चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। वे 2024-25 में तमिलनाडु में 9.69 प्रतिशत ग्रोथ रेट को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गिना रहे हैं।**

टूटा है, तभी बनता है, गठबंधन पार्टनरों के हल्के-फुल्के मतभेद भी हैं, तथा अभिनेता विजय का भी राजनैतिक क्षितिज पर उदय हो चुका है— इस सब कारणों के चलते, स्टालिन आत्मविश्वास से भरे हुये प्रतीत हो रहे हैं, या फिर तमिलनाडु के मतदाताओं के सम्मुख वे स्वयं को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

वे आर्थिक मोर्चे पर राज्य की उपलब्धियों को प्रस्तुत करते ही रहते हैं

तथा अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी वे ऐसी ही उपलब्धियों के वादे कर रहे हैं।

मंगलवार को, विधानसभा में बहस का समापन करते हुये, उन्होंने अपनी सरकार की चार साल की विभिन्न उपलब्धियाँ गिनाईं। स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली इस सरकार के शासनकाल में राज्य ने नई ऊँचाइयों स्पर्श की हैं तथा

तमिलनाडु 9.69 प्रतिशत ग्रोथ रेट के साथ, 2024–25 में “पहले नम्बर” पर रहा है।

स्टालिन ने कहा कि यह ग्रोथ रेट अभूतपूर्व थी। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के आँकड़े इस तथ्य को प्रमाणित कर रहे हैं।

उन्होंने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ बताते हुये कहा कि मिडिल स्कूलों में न कोई ड्रापआउट नहीं” है, गरीबी उन्मूलन के प्रयास जारी हैं तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्टालिन ने कहा कि राज्य में कानून–व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमसे चूक हो तथा कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, लेकिन हमारी उपलब्धियाँ सबके सामने हैं, सबको दिखाई दे रही हैं।

स्टालिन ने पूर्ण भरोसा व्यक्त करते हुये कहा कि तमिलनाडु के मतदाता, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन के कारण, द्रमुक को जबरदस्त समर्थन देंगे।

लेकिन जमीनी स्तर पर, कुछ सत्ता– (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, 29 अप्रैल (निर्स)। शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यह छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहा था और कोटा में रह रहा था। छात्र मूल रूप से बिहार का निवासी

- **बिहार का छात्र 15 दिन पहले ही 11वीं के साथ मैडिकल की तैयारी के लिए कोटा आया था।**
- है और 15 दिन पहले ही कोटा आया था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
- जवाहर नगर थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र के ही एक हॉस्टल से सूचना मिली थी। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे थे और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, साथ ही जांच पड़ताल के बाद बाँड़ी को मोर्चरी में शिफ्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के ‘एक्स’ अकाउंट को भारत में निलम्बित कर दिये जाने, तथा उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जैसे जाने-माने आलोचकों पर एफआईआर किये जाने से सोशल मीडिया युगों तथा सिविल सोसायटी सर्कल्स में बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह सब भाजपा-आरएसएस ईको सिस्टम की गहरे तक पैठी आंतरिक असुरक्षा का संकेत है।

पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों के एक्स एकाउंट भी सस्पेंड किए गए हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इससे पहले, सोमवार को भारत ने 16 पाकिस्तानी यू ट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया था, जो कथित रूप से भड़काने वाली, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तथा

यू.पी. पुलिस ने एक ऐसी एफआईआर एक्टिविस्ट व प्रोफेसर माद्री काकोती के खिलाफ भी दर्ज करवायी

भारत के खिलाफ भ्रामक विषय वस्तु प्रसारित कर रहे थे तथा पहलागम हमले के संदर्भ में भारत की सेना व सुरक्षाबलों के खिलाफ द्वेष फैला रहे थे।

इसी बीच, उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें भारत की सम्प्रभुता, एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करना शामिल है। एक अन्य एक्टिविस्ट माद्री काकोती, जो डॉ. मेडुसा के नाम से विख्यात हैं, पर भी इन्हीं आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

एक भाजपा कार्यकर्ता अभय प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज की थी कि लोक

- **एफआईआर के अनुसार, नेहा सिंह राठौड़ ने अपने एक्स हैंडल पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों की हैं, जिससे देश की अखण्डता को चुनौती मिलती है तथा साम्प्रदायिक तनाव व दुर्भावना फैलने की आशंका है।**
 - **शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह के अनुसार, इन एफआईआर के विरोध में नेहा राठौड़ द्वारा दिये गये वक्तव्य पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं तथा इन वक्तव्यों के आधार पर पाकिस्तान मीडिया भारत के खिलाफ प्रपोगेंडा फैला रहा है तथा भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ सवाल उठा रहा है।**
- गायिका एवं कवयित्री नेहा सिंह राठौड़ अपने एक्स हैंडल का इस्तेमाल कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए कर

का प्रयास कर रही हैं।” इस शिकायत के आधार पर लखनऊ की हज़रत गंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

एफआईआर के अनुसार, नेहा सिंह राठौड़ के भारत विरोधी बयान पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं तथा पाकिस्तान के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया नेहा सिंह राठौड़ के भारत विरोधी सभी बयानों का इस्तेमाल कर रहा है और भारत के खिलाफ बयानबाजी के लिये इन बयानों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे समय में नेहा सिंह राठौड़ के भारत विरोधी बयान देश और सभी कवियों के लिए अपमानजनक है।

एफआईआर के जवाब में राठौड़ ने

कहा, यह एक्शन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया गया है।

नेहा ने कहा, “पहलगाम हमले के जवाब में सरकार क्या कर रही है, मेरे खिलाफ एफआईआर? मेरे खिलाफ एफआईआर कर सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या यह सम्झना इतना मुश्किल है। अगर आप में हिम्मत है तो आतंकवादियों के सिर लेकर आइए अपनी असफलता के लिए मुझे दोष मत दीजिए। जैसे लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही हर सवाल भी महत्वपूर्ण होता है। सरकार को मेरे सवाल पूछने से दिक्कत है, इसलिए वे मुझे रोकना चाहते हैं।”

राठौड़ के बाद, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. मेडसा (माद्री काकोती) के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। डॉ. मेडुसा सरकार की आलोचक हैं और अपने कटाक्षों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **याचिकाकर्ता को 1989 में हत्या के प्रयास के अपराध पर निचली अदालत ने ढाई साल की सजा सुनाई थी। वैसे हाई कोर्ट ने 1989 में ही सजा स्थगित कर दी थी।**
- पेश अपील को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने याचिकाकर्ता ने यह आदेश सलीम और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

श्रद्धा और विश्वास ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जो एक बार घोल कर पी लेता है वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। –अमृतलाल नागर

क्या है सोशल मीडिया का वास्तविक स्वरूप!

मार्शल मैक्लुहान का एक प्रसिद्ध कथन है कि “सभी मीडिया किसी न किसी मानवीय क्षमता का विस्तार हैं– मानसिक हो या शारीरिक”। इस आधार पर हमें सोशल मीडिया को उसके वास्तविक स्वरूप में समझने में मदद मिल सकती है। आभासी ऑनलाइन दुनिया का विस्तार इतना व्यापक है कि कोई आश्चर्य नहीं कि यह हमारी भौतिक ऑफ़लाइन वास्तविकता में भी घुस कर उसे उथल-पुथल कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी कह रहे हैं कि यह “वास्तविकता के पुनर्निर्माण का युग” है। सूचना का अतिभार इतना है कि तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल हो चला है। इसके चलते कुछ विशेषज्ञ यह निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि वर्तमान ‘सूचना युग’ वास्तव में ‘झूठी सूचना का युग’ है, जिसमें सत्य बार-बार बलि चढ़ता है। एक समय था जब समाचार मीडिया संगठनों द्वारा तथ्य को पवित्र माना जाता था। हालांकि यह भी तथ्य है कि पूर्ण सत्य हमेशा ही मीडियाकर्मियों से दूर रहा है, लेकिन उन्होंने जितना संभव हो सके इसके करीब पहुंचने की कोशिश जरूर की। बीबीसी के एक प्रसिद्ध प्रोमो को याद किया जा सकता है जिसमें दावा किया जाता था कि “सत्य के कई शेड्स होते हैं और हम उन सभी को प्रस्तुत करते हैं”। एक नये शब्द ‘पोस्ट-ट्रुथ’ ने 2016 में वास्तविकता के डिक्शनरी में प्रवेश किया। इसे एक विशेषण के रूप में परिभाषित किया गया था, यानि वस्तुनिष्ठ तथ्य जनमत को बनाने में कम प्रभावी प्रभावी होते हैं मगर भावनाओं और व्यक्तिगत विश्वासों को उभारने में अधिक कारगर होते हैं। ‘पोस्ट-ट्रुथ’ को ‘वर्ष का शब्द’ नामित करते हुए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अध्यक्ष ने एक दशक से भी कम समय पहले कहा था: “यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी पसंद एक ऐसे वर्ष को दर्शाती है जो अत्यधिक आवेशित राजनीतिक और सामाजिक प्रवचन से प्रभावित है। समाचार खोत के रूप में सोशल मीडिया के उदय और प्रतिष्ठान द्वारा पेश किए गए तथ्यों के प्रति बढ़ते अविश्वास से प्रेरित होकर, एक अवधारणा के रूप में पोस्ट-ट्रुथ कुछ समय से अपनी भाषाई पैर जमा रहा है।” इसके लगभग एक दशक बाद यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि हम पास्ट-ट्रुथ युग में रह रहे हैं। मगर यह जुमला आम पुराना हो गया है। कभी हमें बताया जाता था कि सोशल मीडिया राष्ट्रीय सीमाओं और सभी बाधाओं को तोड़कर लोगों को एक साथ लाता है तथा वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से सुनिश्चित करता है। इसीलिए स्वतंत्र सोशल मीडिया के आगमन से उत्साहित होकर पत्रकारिता शिक्षा के रूप में प्रतिभाषित किया गया और ऑनलाइन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की होड़ में कूद पड़े। पत्रकारिता और जनसंचार के विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम और डिग्रियां उन पासआउट के लिए नौकरियों के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गईं जो अब न केवल बाजार के उत्पादों बल्कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को बढ़ावा देने के लिए औजार बन कर मजदूरी का जरिया बन गईं। सभी स्वतंत्र पत्रकार हो गये। ऐसे मजदूरों को सम्मानजनक इंफ्लुएंसर का नाम दे दिया गया। केंद्र और राज्यों की सरकारों ने भी उनकी सेवाएं लेना शुरू कर दी है। प्रचार का काम करने वाले अब पत्रकार मान लिए गये हैं।

सोशल मीडिया का आम तक का अनुभव बताता है कि वह कुछ और भी करता है। वह जो कुछ और करता है वह अब बिल्कुल भी रहस्य नहीं है। वास्तव में वह एकता को तोड़ता है और सीधे टकराव की सुविधा देकर लोगों को विभाजित करता है। इसलिए, इसे उचित ही विभाजनकारी मीडिया के रूप में वर्णित किया जाने लगा है जो आम सहमति के प्रयासों की हमारी क्षमता को बाधित करता है। आम सहमति के बिना कोई भी समाज ज्ञान का साझा-निर्माण नहीं कर सकता है। समाज में टकराव के मुद्दों की कभी कोई कमी नहीं होती हैं। हम विवादित पक्षों के अग्रगण्यों को सोशल मीडिया पर आम तौर पर कटु शब्दों वाले द्वंद्व और झगड़ों में लिप्त रहते पाते हैं। यहां दोस्त बनाये जाते हैं और लोगों को अनफ्रेंड भी किया जाता है। सोशल मीडिया कुछ और भी करता है। यह समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय बनाता है। ऐसे समुदायों के लोग एक-दूसरे को हर तरह से पसंद करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स जैसे पटलों पर बने मित्र मोटे तौर पर समान विश्वदृष्टि रखते हैं। समान हित और

बीसवीं सदी के दौरान लंबे समय तक प्रिंट मीडिया और बाद में प्रसारण मीडिया ने समाज और राजनीति को आकार दिया। डिजिटल मीडिया जिसे विशेषज्ञों ने मुक्ति-मीडिया के रूप में देखा वह जिस धमाकेदार तरीके से आया, उसने अचानक पुराने संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामाजिक रूप से विनाशकारी भूमिका के खिलाफ आवाजें सुन रहे हैं।

कहता है कि सोशल मीडिया ने “संचार के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस माध्यम ने सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को आवाज दी है जिनका मुख्यधारा के समाचार मीडिया में बहुत कम प्रतिनिधित्व था या वे अनुपस्थित थे। सोशल मीडिया ने नागरिकों को सरकारों और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन प्रदान किया है।” सोशल मीडिया पर सभी को अपनी बात कहने की आजादी है। कोई भी किसी भी चीज को समाचार कह सकता है। और हर कोई किसी भी चीज को फर्जी खबर कह सकता है, ट्रोल कर सकता है। कोई नहीं जानता कि किस पर विश्वास किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। सोशल मीडिया समाज को आभासी जगत में ले जाता है। मुख्यधारा के भौतिक मीडिया के विपरीत सोशल मीडिया मनोवैज्ञानिक कनेक्शन पर काम करता है। संदेश इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वे भावनाओं को झूठे हैं। सोशल मीडिया, वास्तव में, बाजार उद्यम है। इन उद्यमों का उत्पाद उनके उपयोगकर्ता ‘हम लोग’ हैं। लोगों को उनके प्लेटफ़ॉर्म पर बनाए रखने के लिए एल्गोरिथ्म डिज़ाइन किया जाता है। यदि कोई मोदी विरोधी के रूप में क्लिक करता है, तो एल्गोरिथ्म उसे और अधिक मोदी विरोधी सामग्री दिखाएगा और इसके विपरीत यदि कोई राहुल गांधी विरोध का संकेत देता है तो उसे एल्गोरिथ्म वैसी सामग्री परोसेगा। इस प्रकार लोगों के पूर्वाग्रहों की पुष्टि होती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके दूसरों के प्रति घृणा को बढ़ाया जाता है। सोशल मीडिया का उदय शासन प्रणाली, विशेष रूप से इसकी संस्थाओं, में विश्वास के संकट के साथ हुआ है। एक के बाद एक बड़े वित्तीय घोटालों के साथ मीडिया में लोगों के विश्वास में दीर्घकालिक गिरावट आई है। इसका मतलब है कि जिन बुनियादी संस्थाओं पर लोकतंत्र आधारित है, उन्हें बदनाम किया जाता है। परिणामस्वरूप हम लोकलुभावन जननायकों और राष्ट्रवादी जननायकों का उदय देखते हैं।

पुस्तक वॉर इन 140 कैरेक्टर्स: हाउ सोशल मीडिया इज रीशेपिंग कॉम्प्लैक्ट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के लेखक डेविड पैट्रिकर्क्स कहते हैं कि, “जितना अधिक संदेश आप दर्शकों के मन में सभी सूचनाओं के प्रति जाग सक्ते हैं उतना ही सत्य को पहचानने की उनकी प्रवृत्ति को कमजोर कर सकते हैं। इसका उद्देश्य पुराने युग के राजनेताओं की तरह सत्य को तोड़-मरोड़ कर पेश करना नहीं है, बल्कि इस धारणा को ही खत्म करना है कि कोई वस्तुनिष्ठ सत्य मौजूद है।” अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारा यह विश्वास कि इंटरनेट और डिजिटल मीडिया तकनीक हमें स्वतंत्रता के एक नए युग में ले जाएगी, अब भी सच हो सकता है? मगर अनेकों को लगता है कि “लोकतांत्रिक बदलाव के लिए आशावादी दृष्टिकोण” जो कभी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में निहित था, उसमें से बहुत कुछ खो गया है और अब एक गहरी निराशावादित छा गई है। नागरिक जीवन पर डिजिटल मीडिया के सभी रूपों के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में गहन अनिश्चितता प्रतीत होती है, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जो कई लोगों के लिए आभासी की जगह वास्तविक बन गए हैं। कुछ समाजशास्त्री इसे एक समस्याग्रस्त पहलू मानते हैं कि किस प्रकार डिजिटल मीडिया अपना स्वरूप बदल रहा है, जनमत का निर्माण किस प्रकार हो रहा है तथा उदार लोकतंत्रों की नागरिक संस्कृति किस प्रकार विकसित हो रही है। बीसवीं सदी के दौरान लंबे समय तक प्रिंट मीडिया और बाद में प्रसारण मीडिया ने समाज और राजनीति को आकार दिया। डिजिटल मीडिया जिसे विशेषज्ञों ने मुक्ति-मीडिया के रूप में देखा वह जिस धमाकेदार तरीके से आया, उसने अचानक पुराने संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामाजिक रूप से विनाशकारी भूमिका के खिलाफ आवाजें सुन रहे हैं। कुछ टिप्पणीकार ‘नगरिनी पूंजीवाद’ पर आधारित सोशल मीडिया की एकाधिकार शक्ति की बात करते हैं। राजनीतिक समूहों और कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा उनका उपयोग और दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां हमारा नफरत और असहिष्णुता के प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए, लोगों को, विशेष रूप से मीडियाकर्मियों को, अस्वस्थ सूचना वातावरण से दूर रहकर वास्तविक सूचना स्रोतों से जुड़े रहने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों पर अनजाने में विश्वास न करने और वास्तविक पुस्तकों को भौतिक रूप में पढ़ने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



राजेन्द्र मोहन शर्मा

राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य, गंधीर जल संकट से जूझ रहा है। 68 प्रतिशत रेगिस्तानी भूमि और 400 से 600 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा, जो राष्ट्रीय औसत (1,100 मिलीमीटर) से काफी कम है उस पर ऊपर से अंधाधुंध पानी का दोहन और रेत के धोरों पर भ्रष्टाचार की दियों का अकूत प्रवाह इस संकट की जड़ है। केंद्रीय जल आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता केवल 900 क्यूबिक मीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,545 क्यूबिक मीटर है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 295 ब्लॉकों में से 70 प्रतिशत डार्क जोन में हैं, जहाँ भूजल स्तर लगभग 300 मीटर तक नीचे चला गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की 2024 की स्टडी के अनुसार, पिछले दो दशकों में भूजल स्तर में 2 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट आई है। लूनी

और बनास जैसी नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं। राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, 70 प्रतिशत तालाब और जलाशय सूख चुके हैं या अतिक्रमण और कचरे की भेंट चढ़ गए हैं। गर्मियों में, जब तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, पेयजल की माँग चरम पर होती है तब हमारे पास पहुंचाने को पानी होता ही नहीं है। राजस्थान जल संसाधन विभाग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत हैंडपंप और टयूबवेल गर्मियों में सूख जाते हैं। जल विरादरी की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 60 लाख ग्रामीण परिवार स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। यूनिसेफ की 2024 की स्टडी के मुताबिक, ग्रामीण महिलाएँ और लड़कियाँ अब भी प्रतिदिन 4-6 घंटे पानी लाने में बिताती हैं, जिससे 30 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पातीं। टैकरो की अनियमित आपूर्ति और 500 रुपये प्रति टैकर की कीमत गरीब परिवारों के लिए बोझ है। कृषि पर भी जल संकट की गहरी मार पड़ रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भूजल दोहन के कारण 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादों में कमी आई है। 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि बंजर हो चुकी है, खासकर डार्क जोन ब्लॉकों में, जहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था तब 1.07 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 2024 तक नल से 55

लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय की 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, केवल 60 लाख परिवारों (56 प्रतिशत) को ही यह सुविधा मिल सकी है। अब भी राज्य के 17,000 गाँवों में नल का पानी नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में केवल 29 प्रतिशत घरों में नल का पानी उपलब्ध है। कई जगह पाइपलाइनें बिछाई गईं, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। रखरखाव के लिए फंड की कमी और टूटी पाइपलाइनों ने जल जीवन मिशन को कमजोर किया है।

भ्रष्टाचार ने जल जीवन मिशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये के आवंटित फंड में से लगभग 25 प्रतिशत यानी करीब 3,750 करोड़ रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। काराजों पर 100+ नल कनेक्शन दिखाए गए, लेकिन कई गाँवों में नल का पानी पहुंचा ही नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही, और ठेकेदारों ने निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया, जिससे पाइपलाइनें जल्दी खराब हो गईं। इससे लागत 30 प्रतिशत तक बढ़ाई गई, फिर भी कार्य अधूरे ही रहे।

जल संरक्षण फाउंडेशन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 10 प्रतिशत पाइपलाइन परियोजनाएँ तो केवल कार्गोजों में ही पूरी हुईं। कई जगह पानी की आपूर्ति के लिए पंप या बिजली

कनेक्शन नहीं दिए गए, और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पड़ोसी राज्यों से पानी के समझौते भी आधे-अधूरे हैं। इंदिरा गांधी नहर बीकानेर और जैसलमेर में पंजाब से पानी लाती है, जिससे 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। लेकिन राजस्थान जल संसाधन विभाग की 2024 की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, खराब रखरखाव और चोरी के कारण 30 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है। नर्मदा नहर बांसवाड़ा में गुजरात से पानी लाती है, जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होता है, लेकिन गुजरात के साथ विवाद के कारण यहां भी पानी की आपूर्ति अनियमित है। यमुना का पानी अलवर और भरतपुर के लिए है, लेकिन हरियाणा अपर्याप्त पानी छोड़ता है।

घाघि जल संरक्षण के प्रयासों में कुछ प्रगति अक्षय हुई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ने 2016 से 2025 तक 2.5 लाख जल संचयन संरचनाएँ, जैसे तालाब, चेक डैम, और एनीकट, बनाए गए हैं। झालावाड़ में कालिंसिंध नदी पर बना एक एनीकट 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर रहा है। सीकर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा मिला है। लूनी और बनास जैसी नदियों के पुनर्जनन के लिए छोटे चेक डैम बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास विशाल संकट के सामने नाकाफी हैं। इस संकट से निपटने के लिए ठोस कदमों की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और तृतीय-पक्ष ऑडिट अनिवार्य हों। टेंडर

राजेन्द्र मोहन शर्मा, साहित्यकार, शिक्षाविद और चिन्तक

धर्म गुरुओं को बाल विवाह मुक्त अभियान में जोड़ा

झुंझुनूं, (निसं)। अक्षय तृतीया पर होने वाले अबूझ सावे पर बाल विवाह को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने धर्मगुरुओं को अभियान से जोड़ते हुए उनसे अपील की है कि वे किसी भी नाबालिक की शादी ना करवाएं। झुंझुनूं में इस अभियान का शुभारंभ किया गया।

राजस्थान महिला कल्याण मंडल की जिला प्रभारी चेतना शर्मा ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन तथा एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तहत राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने ना

■ **बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में बढ़ाया कदम. झुंझुनूं में अभियान का शुभारंभ किया**

केवल झुंझुनूं, बल्कि चूरू, नागौर, अजमेर, डीडबना-कुचामन और बीकानेर में इस अभियान की शुरुआत की है। झुंझुनूं को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में पिछले दो सालों से काम किया जा रहा है। जागरूकता से

मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल



विजया रहाटकर

भारत में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक पहल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। पिछले लगभग एक दशक से महिलाओं को उनके अधिकार, सम्मान और हिस्सेदारी दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नैतिकता, ऐतिहासिकता और वैधानिकता के सभी मानकों पर खरा उतरते हुए यह अधिनियम न केवल वक्फ संघतियों के प्रबंधन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के

सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सशक्तिकरण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत में वक्फ के पास लाखों एकड़ भूमि होने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण या अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई थी। यह अधिनियम इन सभी कमियों को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

1. निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी:– पहले बार राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह नारी सहभागिता की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। अब महिलाओं का अनुभव और उनकी प्राथमिकताएं भी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी।

2. महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा:– वक्फ-अलाल-औलद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपत्ति को परिवार के लिए समर्पित किया जाता है। पहले, इस

व्यवस्था में कई बार महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की अनेकड़ें होती थी, सिर्फ घर के पुरुषों को ही उत्तराधिकार का लाभ मिलता था। वक्फ-अलाल-औलद में नई व्यवस्था के तहत अब महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है। संशोधित अधिनियम महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में उनका उचित अधिकार दिलाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती मिलेगी। आर्थिक रूप से सशक्त महिला में सुरक्षा व सम्मान की भावना अधिक होती है।

3. वंचितों के लिए आर्थिक सहायता:–अब वक्फ की आय का उपयोग विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु भी किया जा सकेगा। इससे उन्हें आवश्यक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

4. पारदर्शिता और तकनीकी सशक्तिकरण:–डिजिटल तकनीकों के उपयोग और ऑनलाइन पोर्टलों की स्थापना से महिलाएं अपनी संपत्तियों और कानूनी अधिकारों से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी।

5. विभिन्न मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व:–यह अधिनियम शिया, सुन्नी, बोहरा, अगा खानी समेत सभी मुस्लिम समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

6. शिक्षा और स्वास्थ्य तक व्यापक पहुंच:–वक्फ संपत्तियों के समुचित उपयोग से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ेगा, विशेषकर गरीब और वंचित मुसलमानों को लाभ मिलेगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

7. कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण:–नया अधिनियम कौशल विकास, माइक्रोफाइनेंस, व्यावसायिक शिक्षा, विधवा पेंशन और मुफ्त कानूनी सहायता जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का भी विस्तार करेगा। महिलाओं को उत्तराधिकार, पारिवारिक विवादों और पेरलू हिंसा जैसे मामलों में आवश्यक कानूनी सहायता मिल सकेगी।

राशिफल बुधवार 30 अप्रैल, 2025



पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र सायं 4:18 तक, शोभन योग दिन 12:01 तक, गर करण दिन 2:21 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:15 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज सर्वाथ सिद्धि योग सूर्योदय सम्पूर्ण दिन-रात है। रवियोग सायं 4:18 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 12:48 से आरम्भ होगी। आज आखातीज, अक्षया तृतीया, श्री मातंगी जयन्ती, त्रेता युगादि, कल्पादि है। आज वर्षोत्पत्त समाप्त होगा और रोहिणी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से 9:09 तक, शुभ 10:46 से 12:24 तक, चर 3:38 से 5:14 तक, लाभ 5:14 से सूर्यस्त तक।

राहुकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:53, सूर्यास्त 6:55

मेघ
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बन्ने लगेगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी नहीं है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बन्ने लगेगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बन्ते कार्य बिगड़ सकते हैं।

वृश्चिक
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटक हुए कार्य बन्ने लगेगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

भजनों से किया भगवान परशुरामजी का गुणगान



भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्याधर नगर के परशुराम सर्किल पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। सजे-धजे हाथी, ऊंट, घोड़े, बैडवादन और लवाजमे के साथ भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा निकाली गई जिसमें लोगों ने जयकारों के साथ नाच-गाकर आनंद लिया।

भजनों से किया भगवान परशुरामजी का गुणगान विद्याधर नगर के परशुराम सर्किल पर हुए विभिन्न कार्यक्रम जयपुर। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्याधर नगर के परशुराम सर्किल पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। सुबह वेद मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक कर फूलों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद सामूहिक रूप से सुंदरकांड के पाठ किए गए। पाठ के बाद भजनों से भगवान परशुरामजी का गुणगान किया गया। शाम को जयकारों के साथ संगीतमय महाआरती की गई।

कार्यक्रम से जुड़े विरेंद्र शर्मा और गोपाल शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाईंस विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंददाचार्य सहित अनेक जन प्रतिनिधियों और अनेक गणमान्य लोगों ने सैंकड़ों दीपकों से भगवान परशुरामजी की महाआरती की। इसके बाद सजेधजे हाथी, ऊंट, घोड़े, बैडवादन और लवाजमे के साथ भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में 1100 से अधिक महिलाएं एक ही रंग की साड़ी पहनकर सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाती हुईं चल रही थीं। वहीं युवाओं की टोली वाहन रैली के रूप

में जयकारे लगाते हुए साथ चल रही थीं। शेष सभी लोग हाथों में भगवान परशुराम जी की भगवा पताका और विशाल ध्वज लहराते हुए और जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। फूलों से सजे रथ में विराजमान भगवान परशुरामजी की जगह-जगह आरती उतार कर स्वागत किया गया। ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध लोगबगिच्यों में सवार होकर शोभायात्रा को निहार रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। अलका सिनेमा, सीकर रोड, मुरलीपुरा सर्किल, कैडिया पैलेस चौराहा होते हुए शोभायात्रा रामेश्वरधाम मुरलीपुरा स्थित श्री गौड़ विप्र समाज भवन पहुंची। यहां पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ शोभायात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद भोजन प्रसादी हुई।

बिड़ला सभागार में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 30 अप्रैल को विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की ओर से अभिषेक-पूजन और महाआरती के आयोजन होंगे। विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की ओर से सामूहिक रूप से दोपहर बारह बजे से स्ट्रेच्यु सर्किल स्थित बिड़ला सभागार में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय आयोजन के मुख्य अतिथि लोक सभा अध्यक्ष भीम बिरला, विशिष्ट अतिथि राज्य

सभा सदस्य धनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाईंस विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंददाचार्य होंगे। पूजा-अर्चना के बाद सभी उपस्थित लोगों को देश से आतंक से उन्मूलन करने कासंकल्प कराया जाएगा। प्रारंभ में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने बताया कि समारोह में प्रदेश के करीब बीस संगठन एक साथ भगवान परशुराम का पूजन करेंगे।

राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से विद्याधर नगर सेक्टर चार स्थित भगवान परशुराम भवन में जन्मोत्सव पर पूजा-अर्चना की जाएगी। मुख्य अतिथि महासभा के अध्यक्ष केसरी भंवर लाल शर्मा होंगे। महासभा की सभी इकाइयों की ओर से उनाके कार्यालयों पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राजस्थान गौड़ महासभा की ओर से इसी परिसर स्थित कार्यालय में सादगी पूर्वक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पहलगाम हमले के कारण महासभा ने जन्मोत्सव को धूमधाम से नहीं मनाने का निर्णय लिया था। सर्व ब्राह्मण महासभा ने रेलवे स्टेशन स्थित भगवान परशुराम सर्किल पर पूजा-अर्चना और महाआरती का आयोजन करेंगी। ब्राह्मण समाज राजस्थान की ओर से सीकर रोड ढहर



उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी सहित अनेक जन प्रतिनिधियों और अनेक लोगों ने सैंकड़ों दीपकों से भगवान परशुरामजी की महाआरती की।

के बालाजी कार्यालय पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, औदीच्य ब्राह्मण महासभा, गौड़ विप्र समाज सहित अनेक ब्राह्मण संगठनों की ओर से

भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। स्वेज फार्म स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में बुधवार को भगवान परशुराम की महाआरती होगी। स्वामी

अवधेशाचार्य महाराज के सान्निध्य में होने वाले कार्यक्रम में मालवीयनगर विधायक कालीचरण सराफ और सिविल लाईंस गोपाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।

तस्कर को बीस साल की सजा

जयपुर। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त नौशाद खान को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अभियुक्त की पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पुलिस ने भट्ठा बस्ती थाने में 28 जुलाई, 2018 को एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें कहा गया कि मादक पदार्थ तस्करी करने करने वाला नौशाद भट्ठा बस्ती थाना क्षेत्र में 27 जुलाई, 2018 की रात गांजे की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 20 किलो गांजा उसकी पत्नी की कार से जब्त किया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त और उसकी पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

पंजाब के विकलांगों के लिये जयपुर फुट की स्थापना



शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्री अमृतसर के अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी ने जयपुर फुट के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता, अध्यक्ष सतीश मेहता, गुरु संत रामदास बिवि के कुलपति डॉ. मंजीत सिंह उप्पल और जयपुर फुट अमृतसर केंद्र के अध्यक्ष पूर्व राजदूत नवदीन सुरी की उपस्थिति में जयपुर फुट के केंद्र का उद्घाटन किया।

जयपुर। अमृतसर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट केंद्र की स्थापना हो गई।

इस स्थापना से पंजाब के विकलांगों को अब कुत्रिम पैर सहजता से अमृतसर में ही लगाये जा सकेंगे और उन्हें जयपुर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह जयपुर फुट का देश का

36वां केंद्र है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्री अमृतसर के अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी ने जयपुर फुट के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता, अध्यक्ष सतीश मेहता, गुरु संत रामदास बिवि के कुलपति डॉ. मंजीत सिंह उप्पल और जयपुर फुट अमृतसर केंद्र के अध्यक्ष पूर्व राजदूत नवदीन सुरी की उपस्थिति में केंद्र का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन समारोह में धामी ने डी.आर.मेहता, सतीश मेहता और पूर्व राजदूत नवदीप सुरी के प्रयासों को सराहा। धामी ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से पंजाब के विकलांगों का बहुत राहत पहुंची है। डी.आर.मेहता ने अमृतसर जैसी धर्म नगर में जयपुर फुट केंद्र की स्थापना के लिये धन्यवाद दिया। विशेषकर डीन डॉ.ए.पी.सिंह के प्रयासों की प्रशंसा की।

भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि किसान मोर्चा नरेश टिकैत से पूछना चाहता है कि जो देश हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करवा रहा है।

गुप्ता ने कहा कि इससे पहले भी 19 जनवरी 2022 को पुलिस कमिश्नरेट में तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद स्वामी ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये जिसकी

अंबेडकर जिस वर्ग के उसे कांग्रेस ने दलित माना जबकि भाजपा ने ललित : राजे

जयपुर/इंदौर। पूर्व सीएम वसुन्धरा राजे ने कहा है कि अंबेडकर जिस वर्ग के हैं, उस वर्ग को कांग्रेस ने दलित माना, जबकि भाजपा ने ललित। ललित मतलब सुंदराउनहोंने कहा कि अंबेडकर कहते थे हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे।वे इंदौर के रविन्द्र नाट्यय गृह में आयोजित डॉ. भीम राव अंबेडकर सम्मान अधियान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी जिसमें एमपी के सीएम डॉ.मोहन यादव भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। उनके परिजनों को बाँधे में दाह संस्कार करना पड़ा। उनके सरकारी आवस को प्रधानमंत्री नेहरु ने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। यह मोदी ने किया।बाबा साहेब को भारतनल कांग्रेस ने नहीं,अटल के प्रयास से वीपी सिंह सरकार ने दिया। मोदी जी ने सुप्रीमकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की।

पूरा बीमा क्लेम नहीं देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर 1.1 5 लाख का हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमा क्लेम की राशि का पूरा भुगतान नहीं करने पर हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 1.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही रोकी गई करीब 5.43 लाख रुपए की राशि भी एक माह में लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश इंदु तिवाड़ी की ओर से दायर परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि परिवारी और उसके पति ने विपक्षी बीमा कंपनी से अपनी बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण कराया था। परिवारी के पति की 15 दिसंबर, 2021 को तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में दिखाया गया जहां पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ऐसे में उनकी किडनी प्रत्यारोपण का निर्णय लिया गया। परिवार में कहा गया कि 15 दिसंबर से लेकर 8 नवंबर, 2023 उनके पति अस्पताल में पतों रहे और आखिर

डॉ. रेड्डीज़ और सनोफी हेल्थकेयर ने बेफ़ोर्टस लांच करने के लिए साझेदारी की

जयपुर। विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर, एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेट्रीज़ लिमिटेड ने सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एसएचआईपीएल") के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है ताकि भारत में एक नई दवा, बेफ़ोर्टस (निर्सिबमैब) को पेश किया जा सके। बेफ़ोर्टस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, निर्सिबमैब, एक प्रीफ़िल्ड इंजेक्शन के रूप में शामिल है, जो रैस्पिरेट्री सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) निचले श्वसन पथ रोग (एलआरटीडी) की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, जो नवजात शिशुओं और पहले आरएसवी सीजन में जन्म लेने वाले या उसमें प्रवेश करने वाले शिशुओं के लिए है। यह 24 महीने तक के बच्चों को भी दी जाती है, जो अपने दूसरे आरएसवी सीजन तक गंभीर आरएसवी रोग के प्रति संवेदनशील रहते हैं।

‘मुझ पर न्यायालय में दायर अवमानना याचिका को वापिस लेने का दबाब बनाया जा रहा है’

परेशन होकर मैंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया जिसकी सुनवाई 30 अप्रेल को है : सत्यनारायण गुप्ता

- ‘मुझसे पुलिस अधिकारियों द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया जा रहा है’

शिकायत तत्कालीन मैने डीजीपी को ईमेल द्वारा दी थी, किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद हस्ताक्षरों का दुरुपयोग कर मुझे मेरी ही कंपनी से हटा दिया गया और कंपनी की संपत्तियों को अवैध रूप से खूदबूद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना का मूल कारण मेरी कंपनी सिल्वर सोइल इंडस्ट्रियल पार्क प्राईवेट लिमिटेड है जिसे मैंने वर्ष 2012 में मेरे साझेदार ताराचंद चौधरी थे और पूंजी निवेश के लिये अशोक मुंद्रा को जोड़ा गया। बाद में परिyoजना की सफलता पर मुंद्रा ने मुझे हटाने का षड्यंत्र रचा और मुंद्रा ने प्रमोद स्वामी से मिलीभगत कर मेरे विरूद्ध विद्याधर नगर थाने में चार एफआईआर दर्ज कराईं जिनमें बिना

किसी प्राथमिक जांच के मात्र कुछ घंटों में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इनके बाद तत्काल प्रभाव बनाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिये बाध्य किया गया। इस पर मैंने आईसीआईडीआई बैंक में पत्र लिखकर किसी भी वित्तीय छेड़छाड़ रोकने का आग्रह किया और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों, जयपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया कि मुझसे जबनर इस्तीफा लिया गया है। इसके बाद न्यायालय में भी कंपनी याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय ने 8 मर्चिरता को समझते हुए अंतिम आदेश पारित कर संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। वहीं अशोक मुंद्रा द्वारा दायर दो अपीलों खारिज हो गईं, इससे भी मेरे

दावे की सच्चाई स्पष्ट हो गई। परंतु ताराचंद व मुंद्रा ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी की जमीन को भवानी शंकर सामोता की शेल कंपनी सामोता होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम रजिस्ट्री कर दी, जिसकी अवमानना याचिका मैंने दायर की, जो अब विचाराधीन है। अब मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही हैं और एक के बाद एक झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

सत्यनारायण गुप्ता ने कहा कि इन सबसे परेशान होकर मैंने 18 मार्च को राजस्थान मानवाधिकार आयोग के समक्ष आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप, राजेश शर्मा और प्रमोद स्वामी के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिस पर 4 अप्रेल को आयोग ने कमिश्नरेट से रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई की तिथि 30 अप्रेल को निर्धारित की है।

जमीन विवाद में महिला की हत्या, उपचार के दौरान जयपुर में दम तोड़ा

महिला के देवर और जेठ इस बात को लेकर नाराज थे कि उसके पति ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी

सूरजगढ़, (निसं)। थाना इलाके के स्यालू खुर्द गांव में जमीन विवाद में एक महिला की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार महिला के देवर और जेठ इस बात को लेकर नाराज थे कि उसके पति ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी। घटना सोमवार की है। जब जमीन खरीदने वाला व्यक्ति गांव आया तो महिला के जेठ और देवर अपने परिवार सहित उससे झगड़ा करने पहुंच गए। जब मामला गरम होता दिखा तो जमीन को खरीदने वाला व्यक्ति तो वहां से चला गया, लेकिन आपसी झगड़े में महिला के गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक स्यालू खुर्द गांव में चार भाइयों रघुवीर, दाताराम, निहालसिंह और महेंद्र सिंह की पुश्तैनी जमीन थी। चारों भाइयों ने अपना-अपना हिस्सा बांट रखा था। इसमें से निहाल सिंह ने गत दिनों अपने हिस्से की जमीन सज्जन नाम के व्यक्ति को बेच दी। जिसका पता नेवी में कमांडर महेंद्र सिंह भालोठिया को लगा तो वह गांव आया। सोमवार को सज्जन कुलहार जब निहाल सिंह से मिलने के गांव आया तो महेंद्र सिंह भालोठिया, उसका बड़ा भाई दाताराम, बेटा पवन आदि सज्जन कुलहार की गाड़ी के पास पहुंच गए। दोनों पक्षों में बहस हुई तो मौके की नजकत भांपते हुए सज्जन मौके से चला गया, लेकिन गरमागरमी में निहाल सिंह पर कमांडर महेंद्र सिंह भालोठिया, दाताराम, महेंद्र सिंह का बेटा पवन कुमार और घर की महिलाओं ने हमला बोल दिया। इस मारपीट में निहाल सिंह की पत्नी संतोष के गंभीर चोटें लगी। जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने पहुंचकर मामला शांत कराया और



मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

संतोष को सूरजगढ़ के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर में संतोष ने दम तोड़ दिया। संतोष की मौत की सूचना पर एसएचओ हेमराज मीणा जयपुर पहुंचे। एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया।

इधर, मंगलवार को संतोष की मौत की सूचना के बाद गांव के मंदिर में ग्रामीणों की बैठक हुई। जिसमें इस मामले की निंदा करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निहालसिंह के कोई बेटा-बेटी नहीं है। निहाल सिंह से आए दिन उसका भाई कमांडर महेंद्र सिंह झगड़ा करता था, जिससे परेशान होकर निहाल सिंह अपनी जमीन बेचकर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाह रहा था। तो वहीं कमांडर महेंद्र सिंह और उसका भाई दाताराम, निहाल सिंह के हिस्से की जमीन को हड़पना चाह रहे थे। यही कारण है कि सोमवार को मारपीट हुई,

जिसमें निहाल सिंह की पत्नी की जान चली गई। संतोष देवी का शव देर रात को गांव पहुंचा, जिसका बुधवार सुबह दाह संस्कार किया जाएगा। सोमवार को हुई मारपीट के बाद निहाल सिंह की पत्नी संतोष देवी की हालत गंभीर थी। निहाल सिंह अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए जयपुर चला गया। पीछे से कमांडर महेंद्र सिंह भालोठिया ने थाने में निहाल सिंह, उसकी पत्नी संतोष, जमीन खरीदने वाले सज्जन, उसके एक साथी, पड़ोसी हेमराज तथा उसके दिवंगत भाई रघुवीर सिंह की पत्नी चंद्रकला के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। जिसमें उसने छहों लोगों पर उसके, उसकी पत्नी सुशीला, बेटे पवन आदि के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि निहाल सिंह ने उसके हिस्से का कुआं और रास्ते की सामलाती जमीन को

बेच दिया, जिसके बाद जमीन खरीदने वाला सज्जन लगातार धमकियां दे रहा था। यही कारण है कि वह भी अपनी झूठी से छुट्टी लेकर गांव आया था।

निहाल सिंह ने जयपुर में दी रिपोर्ट 1-इधर, निहाल सिंह अपनी पत्नी का ईलाज करवाने के लिए जयपुर चला गया था। जिसके कारण उसने सोमवार को रिपोर्ट नहीं दी। मंगलवार को उसकी पत्नी की मौत के बाद उसने जयपुर में ही लिखित रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि सोमवार को जब वह अपने घर बैठा था तो उसकी जमीन खरीदने वाला सज्जन आया। इसी दौरान उसका भाई महेंद्र सिंह, महेंद्र की पत्नी सुशीला, बेटा पवन कुमार, दूसरा भाई दाताराम व दाताराम की औरत इन्द्रा पांचो एक साथ होकर हाथों में लाठी सरिया व धारधार हथियार लेकर व महेंद्र सिंह अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर जान से मारने की नयत से उसके घर में

■ जब जमीन खरीदने वाला व्यक्ति गांव आया तो महिला के जेठ और देवर अपने परिवार सहित झगड़ा करने पहुंच गए

घुसकर पहले गाली-गलौच और बाद में मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसका छोटा बेटा अंकित और अंकित की पत्नी निधि व पवन की पत्नी भी पहुंच गई। सभी ने उससे और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान महेंद्र सिंह बार-बार सर्विस रिवॉल्वर लहरा रहा था और जान से खत्म करने की धमकी दे रहा था। इसके बाद उसकी पत्नी से की गई गंभीर मारपीट वह घायल हो गई। जिसकी जयपुर में मौत हो गई।

दोनों की पत्नियां सगी बहनें :-मृतक संतोष देवी और आरोपी महेंद्र सिंह की पत्नी सुशीला देवी, दोनों सगी बहनें हैं। बावजूद इसके जमीन को लेकर दोनों ही पक्षों में लंबे समय से विवाद हो रहा था। महेंद्र सिंह के साथ उसका दूसरा भाई दाताराम भी है। तो निहाल सिंह के साथ उसके भाई की पत्नी चंद्रकला साथ है। निहाल सिंह के भाई रघुवीर का निधन हो चुका है। उसका पूरा परिवार किसी दूसरे गांव में रहता है। विवाद निहाल सिंह के हिस्से की जमीन बेचने पर ज्यादा बढ़ गया। आए दिन होने वाले झगड़े से परेशान होकर निहाल सिंह ने अपने मकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे। जिसमें यह मारपीट की घटना रिकॉर्ड हो गई।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रामगढ़ स्थित ऐतिहासिक मोहर हवेली पहुंची

‘पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवेलियों के संरक्षण के लिए योजना के बारे में तैयारी की जायेगी’

सीकर, (निसं)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को रामगढ़ स्थित ऐतिहासिक मोहर हवेली पहुंचकर हवेली का अवलोकन कर वहां स्थित आर्ट गैलरी का अवलोकन किया।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रामगढ़ शेखावाटी को सीकर जिले में हेरिटेज सिटी और रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़ सहित शेखावाटी रीजन को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रामगढ़ में रुककर लगभग आधा दर्जन से अधिक हवेलियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने रामायण से युक्त छतरियां, फ्रैसको पेंटिंग भित्ति चित्र युक्त हवेली, हेरिटेज धरोहर का बारीकी से अवलोकन किया। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि शेखावाटी में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने पिछले बजट में घोषणा की थी, आज मैं रामगढ़ के द्वी

■ दिया कुमारी ने रामायण से युक्त छतरियां, फ्रैसको पेंटिंग भित्ति चित्र युक्त हवेली, हेरिटेज धरोहर का बारीकी से अवलोकन किया

पर आई हूं, रामगढ़ की हवेलियों के लिए भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि जो हवेलियां बची हुई हैं, उनका संरक्षण करने के लिए क्या प्रावधान ला सकते हैं, इसके बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो ऐतिहासिक हवेलियां हैं, उनको चिन्हित करेंगे कि किन हवेलियों को हम संरक्षण कर उनकी मरम्मत करवा सकते हैं ताकि यहां और अधिक पर्यटक

आ सके। उन्होंने बताया कि राजस्थान में इस साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट शेखावाटी क्षेत्र में पहुंचे हैं, जल्द ही कोई ऐसी कमेटी बनाई जाएगी ताकि इन सुंदर और ऐतिहासिक हवेलियों को बचाया जा सके और इनके माध्यम से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवेलियों के रखरखाव और संरक्षण के लिए योजना के बारे में तैयारी की जायेगी, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की जा सके। इस दौरान पूर्व सांसद झुंझुनूं नरेंद्र खीचड़, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, गोर्वधन सिंह, जिंदर कारंग, पूर्व आईपीएस केशर सिंह, श्रुति पौदार, अतुल खन्ना, रघुवेंद्र सिंह इंडोल, मधुसूदन मालानी, गोवर्धन सिंह, गणेश नारायण शास्त्री, एडीएम भावना शर्मा सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा टीम ने गोदाम से 684 लीटर घी जब्त किया



पुलिस प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की।

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर के नया हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव शक्ति सेल्स गोदाम में बन रहे सरस ब्रांड जैसे उत्पाद की सूचना पर पुलिस प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जहां आईपीएस ऊषा यादव और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेशचंद्र शर्मा ने गोदाम में निरीक्षण किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेशचंद्र शर्मा ने बताया कि मौके से 684 लीटर घी जब्त किया गया तथा डेयरी सरस

■ फेमस ब्रांड के नाम का उपयोग कर खुद के ब्रांड का घी बेच रहे थे

के 2 श्री पार्ष्व घी का 1 और भैरव सरस का 1 सैपल लिया। चारों सैपल जांच के लिए जोधपुर भिजवाए गए। इसके साथ ही यहां मारवाड़ की शान सरस, डेयरी सरस, श्याम सरस, ज्योति

सरस, भैरव सरस, श्री पार्ष्व सरस जैसे कई ब्रांड की के पैकेट और टोन मिले। पाली दुग्ध उत्पादन समिति के सदस्यों को भी मौक पर बुलाया गया। जिन्होंने सीओ सिटी ऊषा यादव को शिकायत दी। जिसमें बताया कि सरस ब्रांड नाम को उपयोग कर यह लोग बाजार में अपनी ओर से बनाया गया घी बेचकर सरस ब्रांड की साख को खराब करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर तीन थाने की पुलिस की टीमें मौजूद रही।

राजकार्य में बाधा के मामले में चार गिरफ्तार

बांसवाड़ा, (निसं)। लोहारिया थाना पुलिस ने पालोदा कस्बे में जानवी हत्याकांड के दौरान रोड जाम कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने व राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में चार को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि 23 मार्च को पालोदा कस्बे में जानवी की हत्या के विरोध में 100-150 व्यक्ति पालोदा बस स्टैंड उदयपुर-बांसवाड़ा हाइवे पर रोड जाम कर सरकारी वाहन पर पत्थर फेंक नुकसान पहुंचाने व पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने पर प्रकरण बीएनएस एवं धारा 3 पीडीपीपी एक्ट में दर्ज कर जांच की गयी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज व गद्दी वृत्ताधिकारी सुदर्शन पालीवाल के निकट सुपरविजन में जांच कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये लोहारिया थानाधिकारी शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। इस टीम ने अभियुक्तों की तलाश की तो ज्ञात हुआ

■ जानवी हत्याकांड के दौरान रोड जाम कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने व राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कार्रवाई की

कि घटना के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिये इधर-उधर छिपते फिर रहे हैं। जिस पर तोड़फोड़ व रोड जाम की घटना करने वालों में से 4 व्यक्तियों को डिटेन कर पूछताछ की गयी तो घटना में शरीक हो रोड जाम व सरकारी वाहन में तोड़फोड़ कर पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करना स्वीकार किया।

जिस पर दिनेश उर्फ पप्पु पुत्र वालजी गामोट निवासी पालोदा, गट्टु उर्फ नरेश पुत्र जीवतराम गामोट निवासी पालोदा, रमेश पुत्र धुलजी भगौरा निवासी पालोदा व रवि पुत्र लालजी माली निवासी पालोदा थाना लोहारिया को गिरफ्तार किया गया।

नानूवाली बावड़ी में सड़क निर्माण कार्य आमजन के लिए परेशानी बना

गांव का रास्ता बंद हो जाने से लोगों को पांच किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी में पिछले काफी समय से चल रहा स्टेट हाइवे का निर्माण कार्य आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। नानूवाली बावड़ी में गांव का रास्ता बंद हो जाने से लोगों को पांच किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही होने से व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है।

■ ठेका कंपनी बिना मैनजमेंट के कार्य कर रही है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है

व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक सैनी ने बताया कि ठेका कंपनी के द्वारा लोगों को परेशानी को ध्यान में ना रखते हुए कार्य किया जा रहा है। सड़क की खुदाई कर देने से नानुवाली बावड़ी के गांव में जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को पांच किलोमीटर का चक्कर लगकर नानुवाली बावड़ी आना पड़ रहा है।



सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही होने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं।

ठेका कंपनी ने रोड की खुदाई करके उसको प्लान नहीं किया और ना ही पानी छिड़का जाता है। अशोक सैनी ने बताया कि दिनभर सड़क से धूल के गुब्बार उठने से दुकानदारों के पूरे दिन मिट्टी दुकानों के अंदर जाती है। वहीं दिनभर सड़क पर जाम का आलम बना रहता है। ठेका कंपनी बिना मैनजमेंट के कार्य कर रही

नौ दिन से लापता बुजुर्ग व्यापारी का कंकाल सड़क किनारे मिला

हाइवे से गुजर रहे राहगीरों ने कुत्तों को कंकाल चबाते देखा तो सिहरन दौड़ गई

■ पुलिस ने पहचान के प्रयास में मिसिंग रिपोर्ट खंगाली तो परिजनों ने आकर बुजुर्ग की पहचान कपड़ों से की

■ लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम करते थे, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

पर उसकी पहचान की। ईचार्ज ने बताया रामस्वरूप के भतीजे प्रकाश ने 24 अप्रैल को सोजतरौड़ थाने में बुजुर्ग की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सोजतरौड़ थाना ईचार्ज जबर सिंह भी मौके पर आ गए थे। इसके बाद परिजन को बुलाया गया। बुजुर्ग की पूरी बांडी को जानवरों नोच रखा था। कपड़ों से

पारिजनों ने शिनाख्त कर ली। अब मामले में मंगलवार रामस्वरूप के भाई मांगीलाल ने शिवपुरा थाने में हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बांडी पाली के बांगड़ हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में रखवाई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। मौके पर एसएपी (पाली) विपिन कुमार शर्मा, सीओ सोजतरसिटी जेद सिंह भी पहुंचे थे। इसके साथ ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। परिजनों के अनुसार, रामस्वरूप बावरी 21 अप्रैल को घर से पाली शहर जाने की कहकर निकले थे। इसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। उन्हें 24 अप्रैल तक जगह-जगह तलाश किया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि कुछ समय पहले ही रामस्वरूप ने अपनी जमीन बेची थी। उसे जमीन का अच्छा दाम मिला था। वह परिचित जरूरतमंदों को ब्याज पर रुपए उधार देता था। विवाहित नहीं होने के कारण उसका खुद का परिवार नहीं था।

श्रीविजयनगर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा

एसडीएम ने 16 बीघा भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले के श्रीविजयनगर उपखंड क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने जांच कर 29 जौबी भी स्थित मुक्का नंबर 28 की 16 बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी काटने की पुष्टि की। इसके बाद उपखंड अधिकारी ने मौके और रिकॉर्ड की यथार्थस्थिति बनाए रखने के आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी

ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 29 जौबी भी क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। यह कार्य काशतकारी शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार बाबूलाल रैगर को जांच के निर्देश दिए गए। जांच में पाया कि खातेदारों द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर विरुद्ध किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई।

उपखंड अधिकारी ने बताया कि खातेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे नैयत तिथि पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही मौके पर स्थिति बरकरार रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों को निर्देशित किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि बिना अनुमति के भूमि उपयोग परिवर्तन अथवा अवैध कॉलोनी विकास की गतिविधियां पाई गईं तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे।

7 5 लाख की लागत से बनी सड़क एक माह में उखड़ी, ग्रामीणों में आक्रोश

■ वाहन चालकों को जान जोखिम में डाल गुजरना पड़ रहा है

नसीराबाद, (निसं)। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते ये कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नसीराबाद क्षेत्र में सामने आया है, जहां लगभग 7.5 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क महज एक माह में ही उखड़ गई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नसीराबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करीब दो माह पूर्व ही पूर्ण किया गया था, लेकिन निर्माण के एक माह के भीतर ही सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे उभर आए हैं और डायर पूरी तरह उखड़ चुका है। वाहन

चालकों को जहां रोज़ाना जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है, वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। देरांदू, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय व आसपास के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा घंटिया सामग्री का उपयोग किया गया और विभागीय अधिकारियों ने निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने से पहले ही लापरवाही दिखाई दी, लेकिन शिकायतों के बावजूद किसी ने संज्ञान नहीं लिया। यह सड़क अभी गारंटी पीरियड में है, ऐसे में निर्माण

एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि वह दोषपूर्ण कार्य की तुरंत मरम्मत कराए। लेकिन जब इस संबंध में विभाग के सहायक अभियंता से संपर्क किया गया तो उन्होंने 'जल्द मरम्मत करवा दी जाएगी' कहकर पल्ला झाड़ लिया। यह सड़क नसीराबाद को देरांदू व आदर्श विद्या मंदिर जैसे प्रमुख संस्थानों से जोड़ती है, बावजूद इसके इस समस्या की ओर न तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान जा रहा है और न ही प्रशासन की कोई प्रभावी कार्रवाई नजर आ रही है। इससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस प्रकार की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तथा घंटिया निर्माण कार्य में लिप्त ठेकेदार, अभियंता और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

आतंकी हमले के विरोध में चनाना कस्बा बंद रहा

सुलताना, (निसं)। पहलापना आतंकी हमले को लेकर आमजन में आक्रोश है। झुंझुनूं जिले में लोग आतंकी घटना का विरोध जता रहे हैं। मंगलवार को चनाना कस्बा बंद रहा। चनाना बन्द के दौरान

■ चनाना बन्द के दौरान सभी बाजार, प्रतिष्ठान, अन्य संस्थान बंद रहे

सभी बाजार, प्रतिष्ठान, अन्य संस्थान पूर्णतः बंद रहे। इसी क्रम में मंगलवार को चनाना कस्बा बंद रहा। व्यापारियों और आमजन ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांग की। विभिन्न संगठनों ने बंद का आव्हान किया था, जिसे व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दिया। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान रखे।

व्यापार मंडल और स्थानीय नागरिकों ने आतंकवादी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने आतंकवाद के ठिकानों पर कठोर और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। चनाना बन्द के दौरान सभी बाजार, प्रतिष्ठान, अन्य संस्थान पूर्णतः बंद रहे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा व नगरीय विकास की समीक्षा की

राजस्थान को, पीएम ई-बस सेवा योजना में 125 अतिरिक्त बसें मिलेंगी- खट्टर

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने पीक आवर्स में बिजली की माँग की आपूर्ति के लिये माँग के अनुरूप विद्युत आवंटन में बढ़ोतरी के लिये केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

जयपुर, 29 अप्रैला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर केन्द्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केन्द्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें। शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हम राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केन्द्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें।

हैं। उन्होंने केंद्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कामना पूल से प्रदेश को आवंटित अस्थायी विद्युत कोटे के रूप में सहयोग देने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया।

शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की पीक आवर्स में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली के आवंटन में बढ़ोतरी का आग्रह किया, जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में, खासतौर से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, राज्य में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।

पीएम कुमुम योजना तथा पीएम

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है।

नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में सीवरेज अनिवार्य रूप से हो तथा आवश्यकतानुसार पुराने और जरूर सीवरेज को बदलने तथा एलाइनमेंट ठीक करने के कार्य भी किए जाएं। बैठक में पीएम ई-बस सेवा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत राजस्थान को 675 बसों का प्रारम्भिक आवंटन हुआ

था। राज्य सरकार के अनुरोध पर अब इसके लिए केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 125 बसें भी दी जाएंगी, जिससे शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा को मजबूती मिलेगी। इस दौरान जयपुर मेट्रो परियोजना, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित, विभिन्न योजनाओं की राज्य में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खार, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नगर सहित, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

लोक गायिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया, जो काफी वायरल हुआ, खासकर पाकिस्तान में।

वीडियो में उन्होंने भारत में धार्मिक आधार पर एकता की कमी के बारे में बात की। हिंदी भाषा के इस वीडियो में उन्होंने कहा कि देश धार्मिक आधार व अन्य मुद्दों पर काफी विभाजित है, दंगे भड़कने में एक सैकण्ड का समय भी नहीं लगेगा। उन्होंने देश के अन्य भागों में रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा की अपील की। उन्होंने कहा कि न्याय किया जाना चाहिए, बदला नहीं।

राठौड़ व काकोती, दोनों को ही सैकशन 196 के विभिन्न उपभागों में गिरफ्तार किया गया है, जो जन्म, जाति, जन्म स्थान, आवास व नागरिकता, भाषा आदि के आधार पर दो समुदायों में नफरत बढ़ाने से सम्बंधित हैं।

मीडिया विशेषज्ञों का मत है कि सरकार द्वारा जो सुधारामक कदम उठाए गए हैं, वे नाकाफी हैं, उनके उल्टे परिणाम हो सकते हैं। सरकार के पास दुष्प्रचार ने निपटने के कई प्रभावी तरीके हैं और ताकत का इस्तेमाल आउट डेटेड हो गया है।

कोटा में एक और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
क र दिया है। छात्र मूल रूप से बिहार के कटिहार का निवासी है। वह 15 दिन पहले ही कोटा आया था और 11वीं के साथ मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। वह अपने एक साथी के साथ रूम शेयर करके रहता था। उन्होंने बताया कि दूसरा लड़का दिनर के लिए चला गया था। जब वापस आया तो छात्र ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उसने हॉस्टल मालिक को बताया। दोनों को शक हुआ तो उन्होंने इस संबंध में तुरंत पुलिस को सूचना दी। हॉस्टल रूम का दरवाजा तोड़कर देखा तो सभी के होश उड़ गए। छात्र को आनन-फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मृतक के चाचा घटना की जानकारी के बाद कोटा पहुंच गए । उनका कहना था कि छात्र के पिता हृदय रोग से प्रसित हैं। उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के ही शव की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा था कि कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं चाहते हैं। इसके बाद, जवाहर नगर थाना पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का कहना था कि बालक अपनी इच्छा से ही कोटा पढ़ने आया था। उसने अपना स्कूल में एडमिशन गांव में ही करवाया था।

मुंबई के स्ववायर मॉल में आग से 100 दुकानें जलीं

मुंबई, 29 अप्रैल। मुंबई से लगे बांद्रा में स्ववायर मॉल बिल्डिंग में मंगलवार सुबह 4.10 बजे आग लगी, जो शाम तक नहीं बुझाई जा सकी। घटना को 16 घंटे बीत चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 के करीब दुकानें जल चुकी हैं। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में 4 मंजिला मॉल के बेसमेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी थी, जो धीरे-धीरे चौथे फ्लोर तक पहुंची। फायर ब्रिगेड को सबसे पहले सुबह 4.50 बजे आग की सूचना मिली थी। पहले इसे लेवल 3 की आग घोषित किया गया था।

जम्मू कश्मीर के 50 पर्यटन स्थल बंद

श्रीनगर, 29 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समूचे केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम 50 रिजॉर्ट्स और पर्यटन स्थलों को 'बंद' कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पिछले सप्ताह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सभी जिलों में किए गए 87 पर्यटन-स्थलों की व्यापक सुरक्षा ऑडिट के बाद लिया गया है।

जस्टिस बीआर गवई 52 वें सीजेआई नियुक्त

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को मंगलवार को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति गवई 14 मई को सीजेआई का पदभार संभालेंगे। मौजूदा सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जस्टिस गवई

■ 13 मई को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जस्टिस गवई 14 मई से कार्यभार संभालेंगे।

उनकी जगह लेंगे। कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका नाम 16 अप्रैल को सिफारिश के रूप में भेजा गया था। जस्टिस गवई का कार्यकाल छह महीने का होगा और वह 23 दिसंबर को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजे बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
57,000 लोगों को निकाल दिया है, क्योंकि मॉल और बाजारों में ग्राहक कम हो गए हैं और उपभोक्ता भावना कमजोर हुई है।

टैक्नॉलजी सेक्टर, जो अमेरिका की सफलता का स्तंभ रहा है, भी सिकुड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन के पहले सौ दिनों में ही इस क्षेत्र से चालीस हजार से अधिक लोगों को छंटनी हो चुकी है। आम

राजस्थान में तेज गर्मी और लू का प्रकोप

मौसम विभाग ने दो मई से गर्मी में राहत की भविष्यवाणी की

जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि एक मई से आंधी एवं बारिश की गतिविधियों के कारण दो मई से लू में राहत मिलने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस जबकि पूर्वी राजस्थान में 40 से 45 डिग्री के मध्य दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में बाड़मेर के अलावा जैसलमेर में 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा जबकि फ्लौदी में 45.2, कोटा में 44.6, जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ में 44.4, वनखली में 44.2, श्रीगंगानगर में 43.8, बीकानेर एवं जालौर में 43.4, भीलवाड़ा में 43.2, चुरू एवं अलवर में 42.2, जयपुर में

‘सेना तय करे कार्यवाही का तरीका, समय और टारगैट’

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही के लिए सेना को खुली छूट दी

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, पीएम ने स्पष्ट किया कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। पीएम ने जोर देकर कहा कि भात आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में मंगलवार एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय

■ मंगलवार को प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ उच्चस्तरीय मीटिंग की, जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, एन.एस.ए. अजीत डोभाल भी थे।

■ इसके बाद प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की। यही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री से मिलने आए।

सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख शामिल थे। बैठक में पहलगाम हमले की विस्तृत समीक्षा की गई और आतंकवाद के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अलग से मीटिंग की। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजी सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इसके बाद संघ संचालक मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से

मिलने पहुंचे। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक भी हो सकती है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीसीएस की बैठक में सेना के ऑपरेशनल प्लान और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत इस हमले का जवाब न केवल त्वरित, बल्कि इतना प्रभावी देगा कि आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट संदेश मिले।

ट्रम्प प्रशासन ने एमेज़ॉन को “ धमकी ”...

अमेरिकियों में इसके खिलाफ व्यापक आक्रोश और विरोध व्याप्त है। कुछ जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। यहाँ तक कि उनके सत्ता ग्रहण करने के बाद से रेटिंग्स में बहुत कमी आई है। इतना ही नहीं, जिन आम मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था, वे अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं, मुख्यतः बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण।

हालांकि, अब भी ट्रंप के कट्टर समर्थक, खासकर र्वेत वर्गस्वामी समूह, मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां दीर्घकाल में अमेरिका के हित में हैं। कई लोग खुश हैं कि वर्षों पहले बंद हो चुकी पुरानी इंडस्ट्रीज फिर से तौट सकती हैं। लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि एक बार जो इंडस्ट्री बंद हो गई, उसे दोबारा खड़ा करना बेहद मुश्किल होता है, खासकर अब, जबकि अमेरिका

की इन्डस्ट्री का इकोसिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। यदि इन्हें पुनः जीवित किया गया तो कई उद्योग बहुत पिछड़ जाएँगे, क्योंकि इन उद्योगों के लिए जरूरी पुर्जें अब देश में उपलब्ध नहीं हैं और श्रम लागत इतनी अधिक है कि उत्पादन आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रह गया है। फिर भी उम्मीद बनी हुई है कि ये उद्योग फिर से फलेंगे-फूलेंगे।

रेलवे भर्ती परीक्षा में पैन, पैंसिल, पानी पर प्रतिबंध

रेल मंत्रालय ने रेल भर्ती बोर्ड के सभी अध्यक्षों को सर्कुलर जारी किया

नयी दिल्ली, 29 अप्रैला भारतीय रेलवे ने रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा पेन, पेंसिल, टोपी, पर्स एवं पानी की बोललाने को भी प्रतिबंधित कर दिया है और हाथों पैरों में मेहंदी लगा कर आने पर भी रोक रेली।

रेल मंत्रालय ने सभी रेल भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों में संशोधन किया गया है। इसमें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की नयी सूची जारी की गई है।

उम्मीदवारों को दिए गए निर्देशों के पैरा 7 (1) में कहा गया है कि प्रतिबंधित वस्तुएं/इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, इयरफोन, ब्ल्यूथूथ युक्त डिवाइस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड,

■ परीक्षार्थी सिर्फ ई कॉल लैटर के साथ ही आ सकेंगे, पैन भी उन्हें परीक्षा हॉल में ही उपलब्ध करवाया जाएगा।

कैलकुलेटर, पुस्तक, पेन, कागज, पेंसिल, ई-यूजर, पाउच, स्केल, राइटिंग-पैड, बेल्ट, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक/खुले खाद्य पदार्थ आदि परीक्षा केन्द्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

परिपत्र के अनुसार परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर की अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र के अंदर कोई पेन/पेंसिल नहीं ले जाना है।

‘सफल इकोनॉमिक्स, सफल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
विरोधी सोच भी पनप रही है तथा, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों पर दो मंत्रियों को हटाये जाने के बाद, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार की नकारात्मक छवि भी बनी है। उल्लेखनीय है कि उक्त मंत्रियों को हटाये जाने का कदम अदालतों तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के दबाव के चलते उठाया गया था। और अब एक अन्य मंत्री पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तथा राजनैतिक हलकों में ऐसी चर्चाएँ हैं कि इस तीसरे मंत्री को भी बखास्त किया जायेगा।

लेकिन द्रमुक के लिये सौभाग्य का विषय यह है कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार चुनाव हारने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। अन्नाद्रमुक प्रमुख स्व. जयललिता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिनमें वे बाद में दोषी भी सिद्ध हुईं, लेकिन तमिलनाडु के मतदाताओं ने उन्हें लगातार दो बार विजयी बनाया तथा 2011 एवं 2016 के दो लगातार

कांग्रेस के पोस्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
यू-टर्न्ड चैनलों और सोशल मीडिया अकाउन्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कई शीर्ष पाकिस्तानी समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें डॉन न्यूज, ए.आर.न्यूज, न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज शामिल हैं।

इन्टरनैट सामग्री की निगरानी करने वाले अधिकारियों का कहना है कि कुछ पाकिस्तान-आधारित सोशल मीडिया हैंडल, खासकर विदेशों में रहने वाले लोगों को निशाना बनाकर, ब्रेनवॉश करने वाली सामग्री डालते हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय राय को प्रभावित किया जा सके। सरकार के सूत्रों ने कहा कि इस

तरह के प्रयासों का उद्देश्य पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है।

इजरायल की रणनीति से प्रेरणा लेते हुए, भारत सरकार भी एक वीडियो शृंखला जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ लंबे समय से जारी आतंकवादी हमलों को उजागर किया जाएगा। राजा संघर्ष के दौरान, इजरायल ने हमاس की बर्बरता को उजागर करने के लिए वीडियो जारी किए थे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा है, “यह एक व्यापक युद्ध है, जो बंदूकों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, नैरेटिव्स और धारणाओं के जरिए लड़ा जा रहा है।”